

मंदिर और सूने मकानों में चोरी करने वाले दो बदमाश दबोचे

जयपुर। खोराबीसल पुलिस ने मंदिर और सूने मकानों में चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शालिर आरोपियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शनि मंदिर से चोरी किए गए चांदी के तीन छत्र तथा एक मकान से चोरी की गई पानी की मोटर बरामद की है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि 25 जुलाई को नांगल जैसा बोहरा स्थित शनि मंदिर (देव तलाई) से चांदी के छत्र चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच के दौरान घटनास्थल और बैनाड रोड के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनके आधार पर राकेश प्रजापत (21) निवासी झामदा कला (चाकस), हाल निवासी कश्चनी की पहचान हुई। आरोपी पहले से कश्चनी थाना क्षेत्र के चोरी के मामले में जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गुप्तताऊ की, जिसमें उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी किए गए तीनों चांदी के छत्र बरामद कर लिए गए। आरोपी को खिलाफ पहले भी चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज है। वहीं दूसरे मामले में 20 जुलाई को ग्रीन पार्क, नांगल जैसा बोहरा निवासी राकेश कुमार ने मकान से औजार, लाइट का सामान और करीब 10 हजार रुपये की पानी की मोटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबि की सूचना के आधार पर सुनील लोरा (26) निवासी नारायण नगर, दादी का फाटक (शोटवाडा) को भेरूजी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया।

पुलिस ने शुरु किया ‘‘ऑपरेशन चौकस’’

जयपुर। राजधानी के पश्चिम जिले में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जयपुर पश्चिम पुलिस ने ऑपरेशन चौकस अभियान शुरू किया है।

‘‘आपकी सूचना, हमारी कार्रवाई’’ थीम पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत आमजन से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 7300012212 व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ने बताया कि इस नंबर की सीधी निगरानी डीसीपी कार्यालय करेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति को पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त प्रत्येक सूचना का सत्यापन कर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री, अवैध हथियारों के निर्माण और खरीद-फरोख्त, जुआ-सट्टा तथा गुंडागर्दी एवं अन्य अस्माजाजिक गतिविधियों की सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि आमजन की सक्रिय भागीदारी से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा और समाज को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

तेज रफ्तार एस.यू.वी. ने स्कूटी सवार छात्र को रौंदा

पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में वंदेमातरम मार्ग पर हुआ हादसा, चालक फरार

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र के वंदेमातरम मार्ग पर बारिश के दौरान तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार 19 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई और उसका टायर फटने पर चालक कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो गुरुवार को सामने आया।

थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान विरुपक्ष उर्फ राजा मीणा (19) निवासी सूर्य नगर, गोपावपुरा बाईपास रूपा में हुई है। जो बारिश के दौरान स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आई एसयूवी ने उसे सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एसयूवी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसका

अगस्त तक 1200 पेयजल योजनाओं का होगा जल अर्पण, 2500 गांव होंगे लाभान्वित

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल जीवनमिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा जल अर्पण दिवस के आयोजन को

‘हर जिले में ड्रग से जुड़े 1 0 प्रमुख केस और 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं की होगी सूची तैयार, सम्पत्ति होगी जब्त’

मुख्य सचिव ने प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को सख्त एवं समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी पुलिस थानों में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ड्रग्स की जब्त और तस्करो के विरुद्ध अभियान की और अधिक तेज किया जाए। साथ ही, जब्त ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों को प्रदेश के सभी पुलिस थानों मे एक दिन एक साथ विशेष अभियान चला कर नष्ट किया जाए।

उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों के विरुद्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित मजबूत चार्जशीट



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई।

तैयार की जाए, जिससे न्यायालय में प्रभावी पैरवी हो सके और दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाई जा सके। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को केन्द्र सरकार की ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डैस्ट्रॉय’ नीति के आधार पर ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क को समाप्त

करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए योजनाबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई की जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक ड्रग्स से जुड़े 10 प्रमुख मामलों की सूची तैयार करें

तथा उनमें से 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में वर्ष 2026-29 के लिए मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य

प्राकृतिक खेती में राजस्थान बना मिसाल : क्लस्टर गठन में दूसरा, कृषक पंजीकरण में तीसरा स्थान

राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का दिख रहा प्रभावी असर

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ढाई लाख किसानों को जोड़कर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 2 हजार 380 क्लस्टर गटित किए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देशभर में सर्वाधिक है। इन क्लस्टरों से प्रदेश के 2 लाख 12 हजार 346 किसान जुड़े हैं, यह संख्या आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक है। साथ ही, अब तक राज्य के लगभग 91 हजार 166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा चुकी है, जो राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक लगभग 49 करोड़ 97 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रदेश में 50 हजार

- 2 लाख से अधिक किसान कर रहे हैं 91 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती**
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से मिल रहा उत्तम प्रशिक्षण-उन्नत विपणन**
- मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी, किसानों का उत्पादन बढ़ा, लागत घटी**

किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक किसानों के माध्यम से जैविक खाद उत्पादन के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किया जा रहे हैं, जिससे किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

राज्य सरकार पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 हजार 856 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य की गोशालाओं को दिया गया है। बजट 2025-26 में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में सेंट ऑफ कैंथीलेंस फॉर नैचुरल फार्मिंग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर 2024 को प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है। यह मिशन केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रमाणन और विपणन की समग्र सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसके तहत देशभर में 527 कृषि विश्वविद्यालय, 194 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान तथा 18 उ्कृष्टता केंद्र मिशन अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दो वर्षों तक उपलब्ध करवाई जा रही है। नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक

कानून व्यवस्था कि बिगड़ी स्थिति का जिम्मेदार कौन, किसकी है जवाबदेही? : नेता प्रतिपक्ष

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने प्रदेश में लगातार कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भावपा सरकार, आम जनता को यह विश्वास दिलाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है कि वह अपराध नियंत्रण पर गंभीर है। प्रदेश में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही है और बेखोफ अपराधी

खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।जुली ने कहा कि राजस्थान में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अपराधी बेखोफ होकर अपराध कर रहे हैं। प्रत्येक में एक मामूली विवाद में मानसरोवर इलाके में चार गुंडों ने एक युवक की पीट-पीट कर जान ले ली। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों ही जयपुर से विधायक हैं,

उसके बावजूद राजधानी में कानून-व्यवस्था का यह हाल है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों में इतना दुसाहस कैसे हो रहा है? सरेशा किसी की जान कैसे ली जा सकती है? अभी कुछ दिन पहले ही इसी घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक नाइट क्लब में रात के 3 बजे सरेआम पार्टी चल

- राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कार्ययोजना बनाई। सभी पुलिस थानों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर जब्त ड्रग्स को नष्ट करें : वी. श्रीनिवास**

सचिव ने संबंधित विभागों को इस संबंध में ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा युवा मामलात विभाग को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समन्वित रूप से नशा मुक्ति, जागरूकता एवं ड्रग तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जांच के दौरान

फर्जी आईटीसी के बड़े मामले का खुलासा

जयपुर (कासं)। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मानसरोवर वित्तार स्थित केसर नगर क्षेत्र में संचालित मेसर्स नय्यता पर बड़े कार्रवाई की गई। विभाग की डेटा एनालिटिक्स एवं जोखिम विश्लेषण प्रणाली से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की गई इस कार्रवाई में प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि फर्म द्वारा जीएसटी कानून के प्रावधानों के विपरीत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया है। जांच में सामने आया कि यह फर्म मुख्य रूप से मैनापावर सप्लाई, स्टाफिंग तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करती है।वित्तीयवर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान फर्म द्वारा दिल्ली स्थित विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त खरीद के आधार पर 1.39 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर उसका उपयोग किया। विभागीय सत्यापन में पाया गया कि जिन आपूर्तिकर्ताओं के आधार पर यह आईटीसी लिया गया, उनके जीएसटी पंजीकरण की तिथि से ही निरस्त पाए गए, जिससे इन लेन-देन की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है।

प्रारंभिक जांच के आधार पर 1.39 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट च्छिहित किया गया है। साथ ही, फर्म के क्रेडिट लेजर में 27.47 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्तमान में उपलब्ध पाया गया है।

जब्त किए गए वाहनों की नियमानुसार शीघ्र नीलामी की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन आरोपियों के विरुद्ध तीन या उससे अधिक अपराधिक मामले लंबित हैं, उनके प्रकरणों का प्राथमिकता से शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस दौरान एनटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विकास कुमार ने बैठक का प्रस्तुतीकरण दिया।बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सांवत, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांछा, एएनटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम. एन., रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक, केंद्रीय नाकोटिक्स ब्यूरो, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इंटरलिजेंस ब्यूरो, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कृषि, राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

राज ममता कार्यक्रम के तहत वेब एप बनेगा मानसिक स्वास्थ्य में सहायक

जयपुर । चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के तहत अव्यवह चिंता और आत्महत्या आदि की रोकथाम के लिए राज ममता कार्यक्रम चलाए जाने की की गई बजट घोषणा की गई थी, इसी कड़ी में प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ एवं साक्ष्य-आधारित बनाने की दिशा में चिकित्सा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठीइ ने बताया कि राज ममता कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जयपुर, जोधपुर मेंडिक्ल कॉलेज और एम्स जोधपुर में वेब आधारित टूल किट ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल लागू किया जाएगा। यह वेब-आधारित डिजिटल

एप मरीजों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर एवं वैज्ञानिक पहचान सुनिश्चित करेगा, जिससे उपचार में तेजी आएगी और विशेषज्ञ सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्टर के सहयोग से उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। राठीइ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक वेब-आधारित डिजिटल असेसमेंट टूल है, जिसके माध्यम से मरीज का निर्धारित प्रश्नों के आधार पर साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार पूरा होते ही सिस्टम स्वतः रिपोर्ट तैयार करेगा।

सार-समाचार

पशु चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण

जयपुर । पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना के निर्देश पर विभागीय अधिकारी इन दिनों पशु चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार को विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एक दल ने जयपुर जिले की तीन पंचायत समितियों के सात पशु चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पशु चिकित्सालयों एवं उपकेंद्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा भंडारण, स्वच्छता व्यवस्था, उपकरणों की उपलब्धता, अभिलेखांश प्रणाली तथा पशुपालकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण दल ने संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित उपस्थिति, उपचार व्यवस्था तथा पशुपालकों से बेहतर संवाद बनाए रखने के संबंध में चर्चा की। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। डॉ। संजय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधातात्मक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों में कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, जिन संस्थाओं में अनियमितता पाई गई है वहां भी संबंधित कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। दल ने जिन संस्थानों का निरीक्षण किया उन्होंने चाकस पंचायत समिति के बाडा पदमपुरा का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेंद्र, बापूगांव, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कोखावदा, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय फागी, तथा पंचायत समिति माधोराजपुरा के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय कादेडा और पशु चिकित्सा उपकेंद्र डाबीच शामिल हैं।

तीन विधानसभा कार्मिक सेवानिवृत्त

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा के तीन कर्मियों सहायक लेखाधिकारी नरसी राम गुर्जर, सहायक कर्मचारी आनन्द व्यास और राजकुमार पंवार को सेवानिवृत्ति पर साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी। देवनानी ने कहा कि विधान सभा में सभी के प्रति समभाव है। उन्होंने कहा कि उनके स्पीकर पद के कार्यकाल में विधान सभा कर्मियों का यह 25 वर्ष सेवानिवृत्ति समारोह है। वे सभी समारोह में व्यक्तिः मौजूद रहे। इन समारोह की सुखद अनुभूति यह है कि यहां सहायक कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक का सेवानिवृत्ति समारोह एक जैसा आयोजित किया जाता है और विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी इन समारोह में मौजूद रहते है। इस मौके पर राजस्थान विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव संजीव शर्मा, वित्तीय सलाहकार अमूर्त जोशी और राजस्थान विधान सभा कर्मचारी सहकारी साक्षा समिति के अध्यक्ष रवि जैन सहित विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। समारोह का संचालन दुर्गादास मूलचंदानी ने किया।

मुरली मनोहर अर्किचन महाराज का सम्मान

जयपुर । छोटी काशी के प्रख्यात कथावाचक मुरली मनोहर अर्किचन महाराज को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत कृष्णा नगर द्वितीय, लालकोठी में आयोजित सम्मान समारोह में जय श्रीनारायण परिवार की ओर से वंदा गुरुदेव श्री श्यामसुंदर आचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान इन्द्र मण्जिजी महाराज ने प्रदान किया। समारोह में आदित्य वर्धन, गिरधर शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। सम्मान पत्र का वाचन करते हुए कहा गया कि महाराज ने ‘‘पीबत भागवतं रसमालावतं’’ की भावना को साकार करते हुए देशभर में लगभग 5०0 भाववत कथाओं के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक चेतना का संसार किया है। उनकी ओजस्वी वाणी, सरल एवं प्रभावशाली शैली, सूक्ष्म विश्लेषण तथा गूढ़ आध्यात्मिक विवरण के प्रभावशाली में प्रस्तुत करने की कला ने उन्हें देश के लोकप्रिय कथावाचकों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है।

16 अगस्त तक बड़ी

खरीफ फसलों के

बीमा की अंतिम तिथि

जयपुर । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। इससे अब हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित बनाने, खेती में जोखिम कम करने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अविशुचित प्राकृतिक जोखिमों से फसल क्षित होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन हेतु चार बीमा कंपनियों का चयन किया है, जो विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराएंगी। किसान 16 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, निकटतम बैंक, सहकारी समिति,